(i) Investigation is pending in 14 cases.

(ii) Sanction for prosecution is awaited in 3 cases.

(iii) In 3 cases evidence was not sufficient to file charge-sheet.

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के अधिकारियों की जवाबदेही

4348. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में प्रशासनिक अधिकारियों और सचिवों (आई.ए.एस.) के साथ कीगई बैठक में आई.ए.एस. अधिकारियों की कार्य पालन और कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की सख्त जरूरत पर जोर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा आई.ए.एस. अधिकारियों को ज्यादा जवाबदेही और लोकोन्मुख बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान कार्य प्रणाली काफी हद तक असंतोषजनक है जिसके परिणामस्वरूप असमानताएं बढी हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने की अति आवश्यकता है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर.बालसुब्रमण्यन) : (क) से (घ) दिनांक 20-11-1996 को राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों के मुख्त सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही नहीं बल्कि समग्र रुप से सिविल सेवाओं को साफ-सुथरा बनाते हुए और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करते हुये, संपूर्ण प्रशासन को उत्तरदायी, जवाबदेही और प्रभावी बनाने से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था । इस सम्मेलन को प्रधान-मंत्री द्वारा संबोधित किया गया था जहां उन्होंने प्रशासनिक तंत्र में लोगों की आस्था पुनः स्थापित करने तथा जनाभिमुखी प्रवृत्ति और डिलीवरी प्रणाली को अपनाने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को समर्पित भावना से कार्य करने के लिये प्रेरित किया । सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिश की :-

(i) जनता की संतुष्टि और सेवाओं की उत्तरदायित्वपूर्ण डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिये जवाबदेही को व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए । इस उद्देश्य के लिये यथासंभव अधिक से अधिक सेवा संस्थानों के लिये नागरिक चार्टर की शुरूआत चरणबद्ध ढंग से किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए ।

(ii) सरकार और लोक निकायों के क्रिया-कलापों में खुलापन और अधिक पारदर्शिता लाना आवश्यक है । उदाहरण के लिये,इसके अंतर्गत सूचना और अधिकारी अधिनियम का प्रयास शामिल होगा ।

इस सम्मेलन के बाद, सार्वजनिक संपर्क वाले कई मंत्रालयों ने नागरिक चार्टर तैयार कर लिये हैं तथा और अधिक उत्तरदायी प्रशासन, क्रिया-विधियों के सरलीकरण,शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि के लिये अनेक उपाय शुरू किये हैं । सरकार ने सूचना के अधिकारी और पारदर्शिता के लिये एक कार्यकारी दल का गठन किया है । प्रशासन में सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है ।

Quality Control Tests in Kendriya Bhandar

4349. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:
DR. ALLADI P. RAJKUMAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the quantity of adulterated stocks of basmati rice withdrawn from Kendriya Bhandar outlets and the number of outlets affected;

(b) whether any quality control tests are being done regularly and if so, the number of tests of various commodities done during the last 12 months and the results thereof; and

(c) the action taken against those found guilty?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTERY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAM): (a) No

basmati rice has been found to be adulterated as per the Prevention of Food Adulteration (PFA) Act. The quesiton of withdrawing any stock therefore does not arise. Basmati rice sold by Kendriya Bhandar meets the specifications prescribed in the PFA Act and the same is released for sale only after testing to meet the above specifications.

(b) and (c) Tests are carried out on all goods including rice. The goods not meeting the prescribed specifications are withdrawn and the suppliers cautioned and, in extreme cases the supplies from them are discontinued for specified period. A total of 2319 tests of various commodities were carried out during the year 1996-97, out of which 162 samples failed.

Import of LNG for Power Sector

4350. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT:
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the ONGC, IOC and GAIL are planning to set up any project to import LNG for the power sector;

(b) whether they are also planning to set up more terminals in order to channelise LNG for the power sector in the country;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the details of power projects proposed to be benefited thereby?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Ennore, Mangalore, Cochin etc. have been identified as possible locations for LNG terminals.

(d) NTPCs projects near Chennai and at Kayankulam may utilise gas imported as LNG.

Allotment of Pertol Pumps and Gas Agencies to Ineligible Persons

4351. SMT. BASANTI SARMA:
DR. SHRIKANT RAM
CHANDRA JICHKAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how many cases of allotment of petrol pumps and gas agencies to ineligible persons have been detected during the last three years;

(b) who verifies the eligibility, the OSBs, or the Oil companies;

(c) whether it is a fact that several persons apply for petrol pumps and gas agencies inspite of being not eligible; and

(d) what steps are taken to see that persons not eligible do not get the petrol pump and agencies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) Twelve (12) cases of ineligible persons getting selected on the basis of furnishing wrong information during the last three years have been reported by the oil companies.

(b) Eligibility of a candidate is verified initially by the concerned oil company. It is further checked by the concerned Board before calling the eligible candidates for interviews.

(c) Yes, Sir.

(d) Applicants are required to submit documentary evidence/affidavits in support of their fulfilling the eligibility conditions stipulated in the advertisement and the application from or at the time of interviews as per the directions of the Board. The documents submitted by the applicants are verified by the concerned oil company as also the selection Board to eliminate ineligible applicants to be considered for selection. In spite of adequate safeguard provided in the guidelines, the possibility of some ineligible candidates getting selected